RE. PROVIDING SECURITY TO SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : मुझे दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है . . .(**व्यवधान**)

उपसभापति : क्या दुख हो गया ?

श्री दिग्विजय सिंह : . . . कि बार-बार एक सवाल को इस सदन में उठाने की इजाज़त आपकी तरफ से मिलती है और गृह मंत्री से आश्वासन भी मिलता है, लेकिन उस आश्वासन पर कोई काम नहीं होता है ।

आप सारी चीजों के चश्मदीद गवाह है और यह सदन गवाह है कि जब मैंने श्रीमती रेणुका चौधरी की सेक्यूरिटी की बात यहां पर की थी, तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी यह काम करने जा रहा हूं । . . .(**व्यवधान**)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (बिहार) : एक दफा नहीं तीन दफा ।

श्री दिग्विजय सिंह : तीन दफा — पिछले सत्र में भी यह आश्वासन हम लोगों को मिला था । इस सदन में भी दो बार यह आश्वासन मिल चुका है । पूरा सदन इस पर सहमत था कि श्रीमती रेणुका चौधरी को उनकी सुरक्षा की हिफ़ाजत के लिए सेक्यूरिटी गार्ड दिया जाए । अब सदन दो दिन और चलने वाला है । माननीय गृह मंत्री जी, मुझे दुख है कि आपको जाते समय मैंने रोका था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए आपको रोका था उस समय कि कृपया आप यह बता दें कि श्रीमती रेणुका चौधरी के लिए सेक्यूरिटी गार्ड की व्यवस्था कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे ?

उपसभापति महोदया, मैं आपका भी इसमें दखल चाहता हूं । यह . . . (**व्यवधान**) का कोई मतलब इस सदन में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में भी आप अपनी राय दें । इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : यह गंभीर मामला है और बार-बार . . .(**व्यवधान**)

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब ने शायद इस सवाल को उठाया हो, कोशिश भी की हो । हम जानना चाहते हैं कि रुकावट कौन डाल रहा है, उस सेक्योरिटी में रुकावट कौन डाल रहा है ? अगर खुदा नाखास्ता कोई हादसा हो गया तो क्या रुकावट डालने वाले पर जिम्मेदारी डाली जाएगी ? यानी एक तमाशा है कि एक इतने सीधे खुले सवाल के सिलसिले में किसी की जान खतरे में है, हैदराबाद में हादसा हो चुका है और उसके बाद A Member of this House is left totally exposed to all sorts of dangers. It is very bad. Who is coming in the way?

कौन रुकावट डाल रहा है, यह मेहरबानी करके होम मिनिस्टर साहब बताएं ?

شری سکندر بخت "مدھیہ پردیش" : صدر صاحبہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوم منسٹر صاحب نے شاید اس سوال کو اٹھایا ہو۔ کوشش بھی کی ہو۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ روکاوٹ کون ڈال رہا ہے۔ اس سیکیورٹی میں روکاوٹ کون ڈال رہا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا روکاوٹ ڈالنے والے پر ذمہ داری ڈالی جائے گی ۔ یعنی ایک تماشہ ہے کہ ایک اتنے سیدھے کھلے سوال کے سلسلے میں کسی کی جان خطرے میں ہے۔ حیدر آباد میں حادثہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد

A member of this House is left totally exposed to all sorts of dangers. It is very bad. Who is coming in the way?

کون روکاوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ مہربانی کر کے ہوم منسٹر صاحب بتائیں۔ "ختم شد"

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, रेणुका चौधरी जी का यह मसला सदन में कई बार उठ चुका है । रेणुका चौधरी जी इस सदन की सदस्या हैं और इस सदस्या का ही सवाल नहीं, इस देश में किसी भी भारतमाता के बेटे या बेटी को अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए अगर कोई आवेदन-पत्र सरकार को देती है और सरकार अगर समझती है कि वाकई उसकी जान खतरे में है तो उसको सुरक्षा प्रदान करना सरकार का फर्ज बनता है । जब एक मेंबर आफ् पार्लियामेंट बार-बार सदन में यह बात उठाता है, इससे ऊपर कोई सदन नहीं है जहां इसका फैसला किया जा सकता है । क्या इसके बाद हम चित्रगुप्त के दरबार में जाकर इसकी मांग करेंगे कि उसको सुरक्षा चाहिए ? बार-बार जब सुरक्षा मांगी जा रही है उसके बाद भी कौन अड़चन डाल रहा है, यह जानने की मेरी इच्छा है ? महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या रेणुका चौधरी जी की तरफ से कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला है इसलिए रोक लगा रखी है या इतने मेंबर जब कह रहे हैं तो उसी को आवेदन-पत्र समझा जाए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तुरन्त की जाए । यही हम आपसे आवेदन चाहते हैं ।

---

†[ ] Transliteration in Arabic script.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : Madam, may I clarity the position? . . . *(Interruptions)* . . .

अभी वह बोल रहे हैं । (व्यवधान) वह जवाब दे रहे हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let him reply. We would not have a discussion. He is answering.

SHRI S. B. CHAVAN : There is no scope for any sort of discussion on this. In fact, after giving an assurance on the floor of the House, I have faxed a message to the Chief Minister of Andhra Pradesh. I have also written a d.o. letter to him. I will try to find out if anyone is creating problems for not providing the security. I will personally look into the matter and talk to him and see that security is provided.

श्री दिग्विजय सिंह : सेक्योरिटी दिल्ली में मांगी जा रही है यह बात बहुत गलत है . . . (व्यवधान)

सेक्योरिटी दिल्ली में मांगी जा रही है । . . . (व्यवधान)

डा० संजय सिंह (उत्तर प्रदेश) : दिल्ली में व्यवस्था होने में क्या दिक्कत है?

श्री वी० हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश): मडोदया, एक लैटर आया प्रोटैक्शन के वास्ते . . .(व्यवधान) सैन्ट्रल गवर्नमेंट से एक लैटर स्टेट गवर्नमेंट को लिखे है । . . . (व्यवधान)

Because I was the PCC President, I was a former Minister, a lot of threats are there I wrote two or three letters. Later, the Central Government wrote a letter to the State Government Still I could not get any protection from the State. this is the point . . . *(Interruptions)* . .

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar) : What is the matter with the Andhra Pradesh Government?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मडोदया, सैक्योरिटी की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे । . . .(व्यवधान) हम सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे । . . .(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : सदर साहिबा, मुझे मालूम था कि होम मिनिस्टर ने कुछ कदम उठाए हैं और इसीलिए मैंने सवाल किया था कि रुकावट कौन डाल रहा है । अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि चीफ मिनिस्टर साहब, जो आन्ध्र प्रदेश के हैं वह जान-बूझ कर, रेणुका चौधरी जी उनकी सियासी मुखालिफ हैं, इसलिए जान-बूझ कर उनको रुकावट दे रहे हैं, तो आपकी संस्था उस सिलसिले में क्या कर रही है ? वहां कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में तो आप ही इनको सेक्योरिटी दे सकते हैं ?

شری سکندر بخت " مدھیہ پردیش": صدر صاحبہ مجھے معلوم تھا کہ ہوم منسٹر صاحب نے کچھ قدم اٹھائے ہیں اور اسی لیے میں نے سوال کیا تھا کہ روکاوٹ کون ڈال رہا ہے ۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو آندھرا پردیش کے ہیں وہ جان بوجھ کر رینو کا چودھری جی ان کی سیاسی مخالف ہیں اس لیے جان بوجھ کر ان کو روکاوٹ دے رہے ہیں تو آپ کی سنستھا اس سلسلہ میں کیا کر رہی ہے ۔ وہاں کانگریس کی سرکار ہے اور دلّی میں تو آپ ہی انکو سیکیورٹی دے سکتے ہیں "ختم شد"

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : Madam, we have been discussing this issue a number of times. I could not understand what the Home Minister is saying. There are two issues here. One is that she wanted security in Hyderabad. . . . *(Interruptions)* . . . She needed security in Hyderabad. The State Government will take care of that part. She needed security in Delhi also. Even that the Home Ministry is not able to provide to her. She has been asking for security in Delhi also as a Member of Parliament. Most of the time she is here in Delhi and sometimes she goes to Hyderabad. What about her security in Delhi? Even for that, does she need clearance from the State Government?

SHRI S. B. CHAVAN : So far as Delhi is concerned, if the security is not given to her by this evening, I will definitely take very stern action against the officer responsible for it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That matter is over now.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मैडम, प्रश्न रेणुका जी का ही नहीं है, प्रश्न हनुमंतराव जी का भी बहुत गंभीर है । वह वहां के फॉर्मर पी०सी०सी० चीफ और वहां के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने जो स्थिति बयान की है, मैं समझता हूं कि इससे गंभीर संकेत और कुछ नहीं हो सकता कि उनको सेक्योरिटी मांगे जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिली है । मैं माननीय

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे हनुमंतराव जी के केस पर भी विचार करें ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): That is a Naxalite area. Therefore, there is need to provide security there and the Government must do something about it.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे हनुमंतराव जी की भी सुरक्षा की व्यवस्था करें ।

उपसभापति : ठीक है, रेणुका जी की सुरक्षा का प्रश्न भी हल हो गया और हनुमंतराव जी की सुरक्षा का भी प्रश्न हल हो गया, दोनों का काम हो गया और अब सभी खुश हो गए । श्री आनन्द प्रकाश गौतम ।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : मैडम, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन चल रहा है और सरकार की पूरी मंत्रि परिषद की ओर से अकेले अबरार अहमद साहब यहां बैठे हैं ।

SHRI V. NARAYANASAMY: What about security for Mr. Hanumantha Rao?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will do it I will see that it is done for both.

श्री प्रमोद महाजन : मैडम, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनको निर्देश दें कि वह भी सदन से चले जाएं ताकि बाकी जो सदस्य हैं, वह आपस में चर्चा कर लें । यहां कम-से-कम एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर को आप अगर जीरो-अवर में नहीं रखेंगे तो आप कितनी गंभीरता से उठाए जाने वाले मामलों को लेंगे ?

उपसभापति : गुलाम नबी आजाद साहब आ गए हैं ।

SHRI SIKANDER BAKHT: It is not enough that only during Zero Hour, a Cabinet Minister should be here. As long as the House sits, there has to be a Cabinet Minister here. and it is not the first time that we have raised this matter.

वित्त मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : मैडम, लोकसभा के वोटर वोटिंग थी, इसलिए जो माननीय मंत्री यहां थे वह वोटिंग . . . **(व्यवधान)** . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Abrar Ahmed, I am sorry. This is no explanation.

SHRI SIKANDER BAKHT: Don't take the House for granted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Saheb, please. This is no explanation and I am not going to accept it, because if there was voting in the Lok Sabha, there are many Ministers who belong to Rajya Sabha and they have no business to vote there. They should be here So, that is no explanation. If they are busy in some business in the other House, we accept it. If they are busy somewhere in some meeting, we accept it. But not for voting. So please find another excuse.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): When the voting is there, the Ministers have to be there because the Members tend to run away and the Ministers are required to bring them back.

RE-INORDINATE DELAY IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO SOME S/C, S/T FAMILIES

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri A. P. Gautam.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक ऐसे मसले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे कि अनुसूचित-जाति व जनजाति के सैकड़ों परिवारों की जीविका का प्रश्न जुड़ा हुआ है ।

महोदया, अनुसूचित-जाति व जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लगभग एक साल से ज्यादा हो रहा है, छह सौ पचहत्तर लोगों को दिल्ली प्रशासन द्वारा एस०टी०ए० बस परमिट स्वीकृत किए गए थे, रेड-लाइन बसों के परमिट उन्हें दिए गए थे और सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 95 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 4 प्रतिशत के ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिससे कि वे बसों को खरीद सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें ।

इस मद में भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम दिल्ली को कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए का आवण्टन किया गया था, परन्तु खेद है कि दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने केवल 9 करोड़ रुपये का ही ऋण बांटा और इसमें गंभीर मसला यह है कि 15.8 करोड़ मायने 16 करोड़ रुपया उस विकास निगम ने एक ऐसे जुए के मामले में लगा दिया, जिसके बारे में माननीय सदन में कई बार पूरी सरकार को कलंकित किया गया । वह पैसा केवल ब्याज कमाने के लिए, काफी धन कमाने के लिए उसमें लगा दिया गया क्योंकि उसमें 22 परसेंट ब्याज देने को कहा गया था ।

महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से केवल यहां से 100 लोगों को ही ऋण उपलब्ध कराया जा सका और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने ऋण के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे,